भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

3 अक्टूबर 2011

भाकपा (माओवादी) पर एस्सार कम्पनी से पैसा लेने का इलजाम लगाकर रमन सरकार अपने जन–विरोधी व कॉर्पोरेट–प्रेमी चेहरे को नहीं छुपा सकती!

दण्डकारण्य दण्डकारण्यवासियों का है – टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, नेको, वेदांता का जागीर नहीं!!

हम सभी जानते हैं कि देश के आदिवासी बहुल इलाकों में पिछले कुछ सालों से कॉर्पोरेट लूटखसोट का वहशियाना खेल मचा हुआ है। साम्राज्यवाद, खासकर दुनिया का अव्वल नम्बर दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारों पर नाचते हुए केन्द्र व राज्य सरकारें खनिज सम्पदाओं से भरपूर वन अंचलों को बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर हजारों आदिवासियों को बेघरबार करने पर तुली हुई हैं। इसके तहत दण्डकारण्य के बस्तर क्षेत्र में टाटा, एस्सार, नेको, जिंदल आदि दलाल पूंजीपतियों की कम्पनियां विभिन्न परियोजनाओं को लेकर घुसपैठ कर रही हैं जिसका बस्तरिया जनता शुरू से ही पुरजोर विरोध व बहादुराना प्रतिरोध कर रही है। विकास के नाम पर जारी विस्थापन और विनाश के खिलाफ पूरे देश में चल रहे जनता के जायज आंदोलनों का भाकपा (माओवादी) समर्थन कर रही है और अगुवाई भी कर रही है। मुख्य रूप से कार्पोरेट लूटखसोट की खिलाफत के कारण ही देश का प्रधानमंत्री माओवादियों को 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा' बता रहा है क्योंकि उस पर खाई हुई दलाली के बदले नतीजे दिखाने का दबाव है। खासकर जब समूची पश्चिमी दुनिया में आर्थिक मंदी से उथल–पुथल मची हुई हो, ऐसे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश की अपार प्राकृतिक सम्पदाओं के दोहन पर आमादा हैं। पहले सलवा जुडूम के नाम से और अब ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से चलाए जा रहे फासीवादी दमन अभियानों के पीछे भी दलाल व विदेशी पूंजीपतियों के हित ही छिपे हुए हैं।

एस्सार कम्पनी की बस्तर क्षेत्र में दो परियोजनाएं चल रही हैं जिसका बस्तरिया जनता और हमारी पार्टी शुरू से विरोध करती आ रही हैं। बैलाडीला से लौह चूर्ण को पानी के साथ बहा ले जाने वाली पाइप लाइन परियोजना से प्रमुख रूप से दो नदियों शंखिनी और शबरी का पानी बर्बाद हो रहा है जोकि बस्तर के पानी पर सरासर डाका है। इसके अलावा धुरली क्षेत्र में प्रस्तावित 8 हजार करोड़ रुपए के इस्पात संयंत्र से कई सौ एकड़ उपजाऊ जमीन छीन ली जाएगी। धुरली क्षेत्र की जनता शुरू से ही इस परियोजना का विरोध करती आ रही है। याद रहे कि सलवा जुडूम का सरगना महेंद्र कर्मा ने ग्रामसभा बुलाकर बंदूक की नोंक पर लोगों से दस्तखत करवाकर 'सहमति' का प्रस्ताव करवाया था। टाटा और एस्सार के साथ स्टील प्लांटों पर रमन सरकार ने जब एमओयू किए थे, उसी समय 'सलवा जुडूम' भी शुरू किया गया था। हत्या और आतंक का तांडव मचाकर हजारों लोगों को तथाकथित राहत शिविरों में घसीट ले जाया गया था। टाटा के साथ–साथ एस्सार ने न सिर्फ जुडूम के सरगनाओं को दलाली खिलाई थी, बल्कि तथाकथित राहत शिविरों के संचालन के लिए अपना 'योगदान' भी दिया था। एस्सार के खिलाफ जनता का आक्रोश इस कदर बढ़ा था कि 2008 और 2009 में उसकी सैकड़ों गाड़ियों को जला डाला गया था और उसकी पाइप लाइन को ध्वस्त कर दिया गया। एक शब्द में कहा जाए तो एस्सार की जन विरोधी और लूटखोर परियोजनाओं के खिलाफ हमारी पार्टी की अगुवाई में बस्तरिया जनता समझौताहीन संघर्ष कर रही है।

वैसे तो माओवादी पार्टी पर सैकड़ों या यूं कहें कि हजारों करोड़ रुपए की 'वसूली' का अरोप नया नहीं है। हमारी पार्टी का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में अक्षम शोषक सरकारों द्वारा ऐसी ओछी हरकतों पर उतारू होना उनके वर्गीय चरित्र के हिसाब से अस्वाभाविक भी नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में वाशिंगटन के अपने आकाओं के पास 'केबुल्स' भेजने से कोई झूठ सच नहीं हो सकता, बल्कि इससे इस बात का सबूत मिल जाता है कि माओवादी आंदोलन को कुचलने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों और भारत के दलाल शासक वर्गों के बीच कितना गहरा तालमेल है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश के अंदरूनी मामलों में अमेरिकी साम्राज्यवादियों की दखल किस कदर बढ़ चुकी है और देश की सम्प्रभुता के लिए यह कितना खतरनाक है।

हमारी पार्टी को पैसा देने के फर्जी आरोप में एस्सार के एक मुलाजिम के साथ–साथ लिंगाराम कोडोपी को गिरफ्तार करना और एक एनजीओ पर निशाना लगाना छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे फासीवाद का संकेत है। गौरतलब है कि पिछले साल लिंगाराम को पुलिस ने 'माओवादी प्रवक्ता' बताकर गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। उसका कसूर इतना ही था कि उसने एसपीओ बनने से इनकार किया था। फर्जी आरोप में ही सही, एस्सार के मालिकों और आला अधिकारियों की बजाए किसी छोटे अधिकारी को गिरफ्तार करना भी रमन सरकार की एक और साजिश है। हमारी पार्टी पर झूठे आरोप लगाने और बेकसूर लोगों को फर्जी मामलों में फंसाकर गिरफ्तार करने के पीछे रमन सरकार की मंशा साफ है। एक तरफ जनता को गुमराह कर वह हमारी पार्टी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी की मदद करने वाले लोगों को वह आतंकित करना चाहती है।

प्यारे देशवासियो, एस्सार कम्पनी से हमारी पार्टी द्वारा पैसा लेने का आरोप एक सफेद झूठ है। एस्सार के खिलाफ दण्डकारण्य की जनता का समझौताहीनं संघर्ष ही सच है। हमारी पार्टी के लिए जनता के हित ही सर्वोपरि हैं और 'जल–जंगल–जमीन पर जनता का अधिकार' के प्रति हमारी पार्टी समर्पित है। यह भी सच है हम अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए अपनी वित्तीय नीति के मुताबिक विभिन्न लोगों से चंदे लेते हैं, लेकिन उन दलाल पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके दलाल राजनेताओं से नहीं जिन्हें मार भगाने और जिनकी राजसत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हम लड़ रहे हैं। अपने एक बेटे की शादी पर 25 हजार मेहमानों को बुलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने वाले रमनसिंह को, जिसके मंत्रीमण्डल का एक प्रभावशाली सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल पर 50 करोड़ रुपए की दलाली लेने का आरोप लगा हुआ हो, हमारी पार्टी पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। हम मजदूर–किसानों, छात्र–बुद्धिजीवियों और लेखक, कलाकार और पत्रकारों से अपील करते हैं कि रमन सरकार के इन नीचतापूर्ण आरोपों को कूडे के ढेर में फेंक दें और दण्डकारण्य की जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष का तहेदिल से समर्थन जारी रखें।

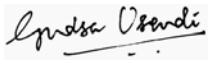

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)